

अमित शाह ने मुख्यमंत्री की पीठ थपथपाई , पेपर लीक समाप्त करने की प्रशंसा की

केन्द्रीय गृह मंत्री ने आरपीए में आयोजित समारोह में आठ हजार नवनियुक्त कांस्टेबलों को नियुक्त पत्र दिए

जयपुर, 1० जनवरी। केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि पारदर्शी तरीके से लोकसेवकों की भर्ती करने से ही कोई प्रदेश आगे बढ़ सकता है और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार ने पूर्ववर्ती सरकार का पेपरलीक का सिलसिला खत्म कर राजस्थान को इससे निजात दिलाई है। उन्होंने कहा कि हमारी राज्य सरकार

- मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि वर्तमान कालखंड देश की आजादी के बाद का अभूतपूर्व कालखंड है, जिसमें देश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का मजबूत व कुशल नेतृत्व मिल रहा है।**

भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता रखते हुए भ्रष्टाचार का उन्मूलन और योग्यता का सम्मान करते हुए राजस्थान के युवाओं को 'बिना सिफारिश और बिना खर्च' के नौकरी दे रही है।

शाह शनिवार को आरपीए में कांस्टेबल नव नियुक्त समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अच्छी कानून व्यवस्था से ही प्रदेश का विकास संभव है। इसे ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार ने पेपरलीक पर रोक लगाने के साथ-साथ



केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह व मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शनिवार को आरपीए में आयोजित कांस्टेबल नव नियुक्ति समारोह को संबोधित किया।

कानून व्यवस्था को मजबूत बनाया और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में राजस्थान को पूरे देश में निवेश का अग्रणी राज्य बनाने का काम भी किया है। इसी का परिणाम है कि आज देशभर के निवेशक राजस्थान की ओर आने की स्पर्धा कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस अवसर पर कहा कि वर्तमान कालखंड देश की आजादी के बाद का अभूतपूर्व कालखंड है, जिसमें देश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह का मजबूत और कुशल नेतृत्व मिल

रहा है। धारा 37० को हटानेक जम्मू-कश्मीर को देश की मुख्यधारा से जोड़ते हुए देश की एकता एवं अखंडता को मजबूती देने का काम किया गया। शर्मा ने कहा कि केन्द्रीय गृह मंत्री ने नक्सलवाद का सफाया करते हुए देश की आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने का काम किया।

शाह ने कार्यक्रम में संकेतिक रूप से 1० आरक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। कार्यक्रम में 8 हजार से अधिक आरक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए

गए। इससे पहले उन्होंने भारत सरकार की खेलो इंडिया योजना के तहत राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर में बने मल्टी परपज इंडोर हॉल का वर्चुअल लोकार्पण किया।

इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा, गृह राज्यमंत्री जवाहर सिंह बेदू म, सांसद मदन राठौड़, मुख्य सचिव वी श्रीनिवास सहित जनप्रतिनिधिगण, पुलिस अधिकाीरगण, बड़ी संख्या में नव नियुक्त कांस्टेबल एवं उनके परिजन उपस्थित थे।

ट्रंप ने ईरान में सैन्य हस्तक्षेप के संकेत दिए परन्तु ट्रंप ने यह भी कहा कि वह जमीन पर सैनिक नहीं उतारेंगे

वॉशिंगटन, 1० जनवरी। अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प ने शुक्रवार को कहा कि अगर ईरान वर्तमान अशांति के इस दौर में लोगों को मारना शुरू कर देता है तो अमेरिका इसमें हस्तक्षेप करेगा, हालांकि वह जमीन पर अपने सैनिकों की नैनाती नहीं करेगा।

ईरान की स्थिति पर संवाददाताओं से बात करते हुए ट्रम्प ने कहा कि अगर वे लोगों को मारना शुरू करते हैं, तो ऐसा होने पर अमेरिका अपनी भूमिका निभायेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि इसका मतलब यह नहीं है कि अमेरिका अपनी फौजें, ईरान की जमीन पर उतार देगा। इसका अर्थ यह है कि उन्हें यहां बहुत जोर से मारना है, जहां सबसे ज्यादा दर्द होता है। ट्रम्प और अन्य वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारियों ने

- ट्रंप ने कहा कि ईरान में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रही जनता पर हमला किया गया तो अमेरिका चुप नहीं बैठेगा।**

बार-बार चेतावनी दी है कि यदि ईरान शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को मारता है, तो वॉशिंगटन कार्रवाई करेगा। ईरान के विदेश मंत्रालय ने बुधवार को अशांति के बारे में ट्रम्प प्रशासन की टिप्पणियों को हस्तक्षेपवादी और भ्रामक बताते हुए उनकी निंदा की थी। ईरान का कहना है कि ये बयान ईरानी लोगों के प्रति अमेरिका की निरंतर शत्रुता को दर्शाते हैं।

एसआई भर्ती ...

गुहार की थी। एकलपीठ ने तीस अक्टूबर, 2०25 को इन अर्थर्थियों को भर्ती में तीन साल की छूट देने को कहा। वहीं राज्य सरकार की अपील पर हाईकोर्ट की खंडपीठ ने अंतरिम आदेश जारी कर गत 13 नवंबर को एकलपीठ के आदेश पर रोक लगा दी थी। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की गई थी।

पुणे निगम चुनाव के लिए सुप्रिया व अजित पवार ने संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया

मुंबई, 1० जनवरी। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एवं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के अध्यक्ष अजीत पवार और राकांपा (एसपी) की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले ने शनिवारको पुणे के शिवाजीनगर में एक संवाददाता सम्मेलन में आगामी नगर निगम चुनावों के लिए अपना संयुक्त घोषणापत्र जारी

- भाजपा नेतृत्व वाले एनडीए के सदस्य होने के बाद भी अजित पवार ने केन्द्र व राज्य सरकार की आलोचना की**

किया। इस संयुक्त घोषणापत्र में पुणे में मुप्त मेट्रो और बस यात्रा का वादा किया गया है।

उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा, “पुणेवासी सवाल कर सकते हैं कि क्या मुप्त मेट्रो और बस यात्रा संभव भी है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यह संभव है। हमने विशेषज्ञों से बात करने के बाद इस में फैसला किया है। हम पुणे और पिंपरी-चिंचवड् के निवासियों को मुप्त मेट्रो रेलवे और बस यात्रा प्रदान करेंगे।”

घोषणापत्र में पुणे नगर निगम के स्कूलों के छात्रों को मुप्त टैबलेट देने के साथ-साथ पुणे में 15० मॉडल स्कूल स्थापित करने का वादा किया गया है।

लोकसभा सांसद सुप्रिया सुले ने कहा, “पुणे के पांच साल के विकास का मुद्दा हमारे सामने है। मुप्त यात्रा प्रदान करना संभव है। क्योंकि सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था के प्रशासन में कुछ गलतियां हैं, जिन्हें दूर किया जाएगा।”

ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को चिट्ठी लिखी

कोलकाता, 1० जनवरी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को एक पत्र लिखकर राज्य में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान आम नागरिकों के साथ किए जा रहे निरंतर उल्टीड़न पर हैरानी और पीड़ा व्यक्त की है।

मुख्यमंत्री ने पत्र में आरोप लगाया है कि इस पुनरीक्षण अभ्यास के कारण 77 मौतें, आत्महत्या के चार प्रयास और कम से कम 17 लोगों के बीमार होने व अस्पताल में भर्ती होने की नौबत आई

देवली में तीन करोड़ रूपए का गांजा जब्त

- पुलिस ने नाकाबंदी कर उड़ीसा से आ रहे ट्रूक में 5०० किलो गांजा पकड़ा।**

किया है। देवली पुलिस थाना प्रभारी दौलत राम गुर्जर ने यह भी बताया कि इस कार्रवाई को अंजाम देने के लिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रतनलाल भार्गव, पुर्बेन्द्र सोलंकी और डीएसपी हेमराज के सुपरविजन में उपनरीक्षक ओमप्रकाश की टीम ने देवली हाईवे पर घेराबंदी की थी। इसी के चलते पुलिस को देखते ही तस्करी ने ट्रक को टोंक की ओर भगाकर ले जाने की कोशिश

ईरान में खामनेई विरोधी प्रदर्शनकारियों पर मशीनगन से गोलियां चलाई

गोलीबारी में 217 प्रदर्शनकारी मारे गये, सरकार विरोधी आंदोलन और उग्र हुआ

- अगर मृतकों की संख्या की सही पुष्टि हो जाती है, तो यह अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के लिए भी चुनौती होगी, क्योंकि उन्होंने पहले ही चेतावनी दी थी कि यदि सरकार 28 दिसंबर से सड़कों पर उतर रहे प्रदर्शनकारियों को मारती है, तो उसे इसका भारी खामियाजा भुगतना पड़ेगा।**

है। प्रदर्शनकारियों की मौत को लेकर स्थानीय डॉक्टर ने बताया कि मृतकों में अधिकतर युवा थे, जिनमें उत्तरी तेहरान के एक पुलिस स्टेशन के बाहर सुरक्षा बलों द्वारा प्रदर्शनकारियों पर मशीन गन से अंधाधुंध फायरिंग करने के दौरान मारे गए कई लोग शामिल थे। इन सभी

की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं, वाशिंगटन डीसी स्थित ह्यूमन राइट्स एंक्टिविस्ट न्यूज एजेंसी, जो सिर्फ पहचाने गए पीड़ितों की गिनती करती है, उसमे विरोध प्रदर्शनों की शुरुआत से अब तक कम से कम 63 मौतों की पुष्टि की है।

ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को चिट्ठी लिखी

- बनर्जी ने नोबल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन, क्रिकेटर मोहम्मद शमी, फिल्म एक्टर व सांसद दीपक अधिकारी जैसी कई हस्तियों का मुद्दा उठाया, जिन्हें चुनाव आयोग के सामने अपनी नागरिकता प्रमाणित करनी होगी।**
- मुख्यमंत्री ने टाइप की हुई चिट्ठी के साथ एक हस्तालिखित नोट भी भेजा है जिसमें उन्होंने लिखा है कि “मुझे” पता है आप ना तो जवाब देंगे ना ही स्पटीकरण देंगे पर विवरण देना मेरा कर्तव्य है।**

है। उन्होंने कहा, "ये घटनाएं डर, डराने-धमकाने और अवैधिक कार्यकार का परिणाम

प्र.मंत्री ने राज्यों के मुख्य सचिवों ...

है। तेज सुधार निवेशकों को आकर्षित कर सकते हैं, लेकिन श्रम बाजार में वैधता और स्वीकार्यता भी जरूरी है। भरोसेमंद सुरक्षा, परामर्श और अमल की क्षमता के बिना ये सुधार एक्टरफम माने जा सकते हैं, भले ही उनका मकसद समावेशी विकास (इन्क्लुसिव ग्रोथ) और रोजगार सृजन हो।

सरकार कुछ हद तक सही संकेत देती है कि यह सुधार चक्र संकट से प्रेरित होने के बजाय आकांक्षा से प्रेरित है और इसमें कुछ सच्चाई भी है। भारत की जनसंख्या संरचना, बढ़ता घरेलू बाजार और डिजिटल ढांचा मजबूत आधार देते हैं। लेकिन केवल आकांक्षा से संस्थागत तैयारी की कमूरी नहीं हो सकती। जिला प्रशासन, नगर निकाय और राज्य नियामक, जो सुधारों को ज़मीन पर लागू करते हैं, अक्सर स्टाफ, विशेष कौशल और डिजिटल क्षमता की कमी से जूझते

हैं। प्रशासनिक क्षमता में निवेश कि ए बिना तेज और गुणवत्तापूर्ण नतीजों की उम्मीद सुधारों के असर को कमजोर कर सकती है और निराशा बढ़ा सकती है।

निजी क्षेत्र के लिए परमाणु ऊर्जा खोलने जैसे बड़े कदम सरकार की मंशा की गंभीरता दिखाते हैं। लेकिन निजी पूंजी बहुत सख्त मानकों पर काम करती है। उसे साफ नियम, भरोसेमंद विवाद, समाधान व्यवस्था और स्थिर नीतिगत माहौल चाहिए। घोषणाओं के साथ विस्तृत नियमावली और संस्थागत भरोसा भी होना चाहिए वरना इनके बदले निवेश आने की जगह संतर्कता और झिझक ही देखने को मिलेगी।

व्यापार समझौते भी बिखरी वैश्विक अर्थव्यवस्था को लेकर व्यावहारिक सोच दिखाते हैं। लेकिन व्यापार उदारीकरण के साथ समायोजन की लागत आती है। लॉजिस्टिक्स, कौशल विकास और सस्ते ऋण में समानांतर निवेश के बिना, खासकर छोटे भारतीय उद्योग खुलते बाजार में टिक नहीं पाएंगे।

आखिरकार, इस सुधार चक्र की मजबूती इस बात पर निर्भर करेगी कि इसके फायदे आम लोगों तक पहुंचते हैं या नहीं। अगर विकास के साफ तौर पर रोजगार, आय में बढ़ोतरी और क्षेत्रीय संतुलन नहीं दिखता, तो सुधारों के लिए जरूरी सामाजिक और राजनीतिक सहमति कमजोर पड़ सकती है। रमत्तर जरूरी है। लेकिन अगर 2०25 को एक ऐतिहासिक साल के रूप में याद किया जाना है, तो यह इसलिए होगा क्योंकि सुधारों को समझदारी से लागू किया गया, संस्थानों को मजबूत किया गया और जनता का विश्वास हासिल किया गया, केवल इसलिए नहीं कि वे तेज चले।

महाराष्ट्र में नए समीकरण ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

सीट बंटवारे में भी सहयोगी दलों की वास्तविक ताकत झलकती है। शिवसेना (यूबीटी) 165 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, मनसे 52 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी, जबकि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार गुट) इस एग गठबंधन के तहत केवल 1० सीटों पर चुनाव लड़ेगी। गठबंधन की घोषणा के लिए एडई संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में ठाकरे भाइयों ने मराठी मानूस को एक सशक्त संदेश देते हुए कहा, बंटेंगे तो कटेंगे, यानी बंटें तो हारेंगे, एकजुट रहे तो जीतेंगे। यह नारा उन्होंने 2०24 के विधानसभा चुनावों में भाजपा के इस्तेमाल किए गए नारे से प्रेरित होकर दिया।

भाजपा-शिवसेना (शिंदे गुट)

गठबंधन ने मराठी मानूस के बीच मजबूत पकड़ बना ली है। एस्कैंडिया स्ट्रैटेंजीस के एक सर्वे के मुताबिक, इस समुदाय का वोट अब 44-42 प्रतिशत के अनुपात में बंट चुका है। वहीं, कांग्रेस के साथ गठबंधन के कारण उड़ब ठाकरे की पार्टी को जो मुस्लिम वोट मिला था, वह एमवीए से अलग होने के बाद स्वतः ठाकरे खेमे में आएगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है।

इसके अलावा पवार परिवार के प्रतिद्वंद्वी भी धीरे-धीरे करीब आते दिख रहे हैं। एनसीपी (अजित पवार गुट) और एनसीपी (शरदचंद्र पवार

माईन मीडिया, बीकानेर के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. 35214/79, जयपुर कार्यालय: सुघर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033, उदयपुर कार्यालय: आर्य मैन रोड आर्यड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, अजमेर कार्यालय:-राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665, जालौर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फैस प्रथम, जालौर। फोन: 226422,226423, फैक्स: 02973-226424
हिण्डोनीसटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डोनीसटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600
चूरू कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908

